बिहार में कोविड-19 के दौरान महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं के वित्तपोषण पर वेबिनार

प्रेस विज्ञप्ति

पटना, 29 सितंबर। आज बिहार सरकार के वित्त विभाग द्वारा यूनीसेफ और आद्री के साथ मिलकर अध्ययन ''बिहार में कोविड-19 महामारी का बच्चों और महिलाओं पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव'' पर आधारित राज्यस्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया।

अध्ययन की संकल्पना और शुरुआत बिहार यूनीसेफ के फील्ड ऑफिस ने की थी जिसे बिहार सरकार और यूनीसेफ के साथ मिलकर आद्री द्वारा विकसित किया गया। अध्ययन का लक्ष्य राज्य में बच्चों पर कोविड-19 महामारी के ज्ञात आरंभिक प्रभाव की समीक्षा करना था। अध्ययन के दो मुख्य हिस्से हैं। पहले हिस्से में बच्चों और महिलाओं पर मुख्य फोकस के साथ स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच की गई है। दूसरे हिस्से में दीर्घकालिक संकट की स्थिति में प्रतिक्रिया की राज्य की क्षमता पर मुख्य रूप से विचार करते हुए अर्थव्यवस्था और राज्य के संसाधनों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन में उपलब्ध प्रकाशित आंकड़ों और अध्ययनों तथा सरकार की सूचना प्रबंधन प्रणालियों (एमआइएस) के आंकड़ों की समीक्षा की गई।

वेबिनार की अध्यक्षता बिहार सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने की। आद्री के निदेशक प्रोफेसर प्रभात पी. घोष ने सहभागियों का स्वागत किया और आलेख की पृष्ठभूमि तथा विकास प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने प्रयास के लिए बिहार सरकार के नेतृत्व को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने बाल बजट निर्माण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संबंध में यूनीसेफ के साथ तकनीकी और वित्तीय सहयोग की भी सराहना की।

बिहार यूनीसेफ के फील्ड ऑफिस चीफ जनाब असदुर रहमान ने अपने आरंभिक वक्तव्य में चुनौतीपूर्ण स्थिति में अध्ययन करने और बहुमूल्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए टीम को धन्यवाद दिया। रिपोर्ट में सर्वाधिक असुरक्षित और सीमांत बच्चों पर महामारी के गंभीर प्रभाव और उसके साथ-साथ अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्तव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभावों को रेखांकित किया गया है। ऐसे समय में समुदायों को प्रभावी ढंग से सहयोग देने के लिहाज से अपनी सेवा प्रदान व्यवस्था को अनुकूलित करने के लिए उन्होंने सरकार के प्रयासों की भीसराहना की। उन्होंने सरकार से बच्चों के लिए स्वास्थ्य पोषण, शिक्षा, जल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई (वाश) तथा संरक्षण सेवाओं को अबाध रूप से जारी रखने का अनुरोध किया।

प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने उद्देश्य प्रस्तुत किए और वेबिनार का संक्षिप्त विवरण सामने रखा।

यूनीसेफ की डॉ. उर्वशी कौशिक और आद्री की डॉ. बर्ना गांगुली ने अध्ययन ''बिहार में कोविड-19 महामारी का बच्चों और महिलाओं पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव'' पर प्रस्तुति दी। उनलोगों ने अध्ययन के उद्देश्य और प्रविधि का संक्षिप्त विवरण सामने रखा और शोध परिणामों की विस्तार से व्याख्या की। उसमें महिलाओं और बच्चों पर विशेष फोकस के साथ बिहार में कोविड-19 के व्यापक समाजिक-आर्थिक प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रस्तुतिकर्ताओं ने जीविका, महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता और बिहार की अर्थव्यवस्था तथा वित्तव्यवस्था पर प्रभाव के विश्लेषण को सामने रखा। डॉ. उर्वशी ने कहा कि ''संकट की जिलावार पहचान करने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने की जरूरत है''। वहीं, डॉ. गांगुली ने कहा कि ''बिहार को लॉकडाउन के दौरान राजस्व का जितना नुकसान उठाना पड़ा वह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 11.5 प्रतिशत के बराबर है''।

प्रस्तुति के बाद पैनल चर्चा शुरू हुई जिसकी अध्यक्षता डॉ. एस. सिद्धार्थ ने की। बच्चों के लिए सेवाओं का जारी रखना सुनिश्चित करने के संबंध में विचारोत्तेजक और सूचनाप्रद चर्चा हुई। पैनल चर्चा के बाद प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित हुआ। उसमें सहभागियों द्वारा रिपोर्ट के शोध परिणामों और प्रेक्षणों से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे गए जिनके उत्तर पैनल की ओर से दिए गए।

पैनलिस्ट 1

अपर प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग श्री अतुल प्रसाद ने कहा कि - ''महिलाओं और बच्चों के अलावा वरिष्ठ नागरिक और भिन्नलिंगी भी संकट से प्रभावित हुए हैं। प्रत्यक्ष लाभांतरण आशा की किरण था जिसने समाज कल्याण विभाग की पूरक पोषहार और अन्य सेवाएं बरकरार रखने में मदद की। समय पर सरकारी प्रतिक्रिया के कारण संकट की गंभीरता में कमी आई।''

पैनलिस्ट 2

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार ने कहा कि, ''सॉफ्रटवेयर तो मौजूद है लेकिन हार्डवेयर की कमी के कारण ऑनलाइन कक्षाओं तक विद्यार्थियों की पहुंच बाधित हुई।'' उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के बाधित होने से कुछ मुख्य सूचकों पर प्रभाव पड़ सकता है।

पैनलिस्ट 3

डॉ. सुब्रत दास ने कहा कि - ''भारत क्रयशक्ति की गंभीर समस्या झेल रहा है जिसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस दौरान संसाधनों की कमी के बावजूद बिहार की प्रतिक्रिया प्रशंसनीय थी।''

पैनल चर्चा के बाद डॉ. सिद्धार्थ ने पैनल में शामिल लोगों को धन्यवाद दिया और सरकारी प्रतिक्रिया के विभिन्न पहलुओं, खास कर कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन से उत्पन्न संकट में कमी के लिए वित्त विभाग की प्रतिक्रिया पर बल दिया। उन्होंने भावी कार्यों की भी विस्तार से व्याख्या की। और अंत में प्रोफेसर प्रभात पी. घोष ने वेबिनार में भाग लेने और इसे सूचनापरक आयोजन बनाने के लिए सभी सहभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

वेबिनार में सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज के सदस्यों और विभिन्न क्षेत्रों के शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

(अंजनी कुमार वर्मा)